of the scheme in 67 centres covering 1,18,600 employees during 1988-89 and 59 centres covering about 140,890 employees during 1989-90.

अनुसूचित जातियों पर अत्याचार की घटनाएं

2690. श्री शरद यादव : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1984 से अब तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात और राजस्थान में अनुसूचित जातियों पर अत्याचार की वर्षवार कितनी घटनाएं हुई ;

(ख) ऐसी घटनाएं कहा-कहां हुई तथा उनका ब्यौरा क्या है ;

(ग) प्रत्येक घटना में दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई तथा यह कार्यवाही किस दाण्डिक उपबन्ध के अधीन की गई ; और

(घ) सरकार ने इस प्रकार की घटनाएं भविष्य में न होने देने के लिए क्या-क्या कदम उठाये है ?

कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुमति ओरांव) : विवरण –I संलग्न है (नीचे देखिए)

(ख) और (ग) इन राज्यों में 1984 से अनुसूचित जातियों पर अत्याचारों की हुई घटनाओं की कुल संख्या 57399 है। घटना स्थलों के नाम जैसे ब्यौरे देना बहुत विशाल कार्य हो जाएगा। ये ब्यौरे राज्यों द्वारा रखे जाते हैं। फिर भी, इन घटनाओं के श्रेणी-वार ब्यौरे विवरण –ii पर संलग्न हैं। (नीचे देखिए)

(घ) सरकार अनुसूचित जातियों पर अत्याचारों के बारे में अत्यधिक चिन्तित है और इस खतरे को समाप्त करने के लिए कृत संकल्प है। अनुसूचित जातियों के विरुद्ध अपराधों के साथ प्रभावी ढंग से निपटने तथा इस महत्वपूर्ण समस्या को सुलझाने के लिए प्रशासनिक तंत्र को तीव्र करने की दृष्टि से राज्य सरकारों को समय-समय पर एहतियाती, निवारक, दंडात्मक तथा पुनर्वासात्मक उपायों संबंधी व्यापक दिशा-निर्देश दिए गए है जिसमें अनुसूचित जातियों के विरुद्ध अपराधों की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए संवेदनशील क्षेत्रों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों को तैनात करना शामिल है। अनुसूचित जातियों के विरुद्ध अपराधों की वार्षिक रूप से समीक्षा भी की जाती है तथा जहां कहीं आवश्यक हो, मामले को संबंधित राज्य के साथ उच्चतम स्तर पर उठाया जाता है।

विवरण I

बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश में 1984 से गैर-अनुसूचित जातियों के सदस्यों द्वारा अनुसूचित जातियों पर किए गए अत्याचारों की घटनाओं की वर्षवार संख्या

राज्य	1984	1985	1986	1987	1988 (तक)
बिहार .	1845	1452	1633	1271	596 (जून)
गुजरात .	582	750	649	727	519 (सितंबर)
मध्य प्रदेश .	5537	5133	4421	2879	1802 (मई)
राजस्थान .	1648	1437	1481	1465	1169 सितंबर)
उत्तर प्रदेश .	4200	4135	4697	4348	3023 (अगस्त)
	13812	12907	12881	10690	7109

विवरण II

"अनुसूचित जातियों पर अत्याचार की घटनाएं" के संबंध में श्री शरद यादव द्वारा पूछे गए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं० 2690 दिनांक 2-12-88 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण।

बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश में 1984 से गैर-अनुसूचित जातियों के सदस्यों द्वारा अनुसूचित जातियों पर किए गए अत्याचारों की घटनाओं की वर्षवार तथा श्रेणीवार संख्या।

राज्य/अपराध का स्वरूप	बताए गए अपराधों की संख्या				
	1984	1985	1986	1987	1988 तक
बिहार :					**जून तक**
हत्या . .	95	54	56	55	37
घातक चोट .	179	110	111	105	41
बलात्कार .	83	63	77	56	34
आगजनी .	201	142	176	145	65
अन्य अपराध .	1287	1083	1213	910	419
कुल .	1845	1452	1633	1271	596
गुजरात :					**सितंबर तक**
हत्या . .	13	22	18	13	11
घातक चोट .	63	64	60	77	38
बलात्कार .	10	09	09	18	11
आगजनी .	12	51	18	17	06
अन्य अपराध .	484	605	544	602	453
कुल : .	582	750	649	727	519
मध्य प्रदेश :					**मई तक**
हत्या . .	122	75	93	71	31
घातक चोट .	351	347	220	153	107
बलात्कार .	213	194	183	139	98
आगजनी .	192	196	108	91	69
अन्य अपराध .	4659	4321	3757	2425	1497
कुल : .	5537	5133	4421	2879	1802

राज्य/अपराध का स्वरूप	बताए गए अपराधों की संख्या				
	1984	1985	1986	1987	1988 तक
राजस्थान :					सितंबर तक
हत्या . .	24	29	43	**35**	**19**
घातक चोट .	192	167	156	205	**96**
बलात्कार .	63	101	106	**115**	**64**
आगजनी .	94	66	61	**45**	35
अन्य अपराध .	1275	1074	1115	1065	955
कुल : .	1648	1437	1481	1465	1169
उत्तर प्रदेश :					अगस्त तक
हत्या	213	223	270	235	182
घातक चोट .	580	582	754	806	501
बलात्कार .	176	177	229	208	158
आगजनी .	377	408	489	404	196
अन्य अपराध .	2854	2745	2955	2695	1986
कुल : .	4200	4135	4697	4348	3023

Assistance for enhancing capacity of providing drinking water

2691. SHRI S. S. AHLUWALIA: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether any offer has been received from any of the organisation to assist India to enhance the capacity to provide more drinking water and to contain endemic diseases;

(b) if so, the precise nature of the help offered;

(c) whether the States have been intimated to take advantage of this offer; and

(d) if so, how many States have since responded thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI JANARDHANA POOJARY): (a) No, Sir.

(b) to (d) Does not arise.

Recommendation of the Technology Mission of oilseeds

2692. DR. NARREDDY THULASI REDDY: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state the recommendations of Technology Mission on oilseeds?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF AGRICULTURAL RESEARCH AND EDUCATION IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI HARI KRISHNA SHASTRI): The objective of the Technology Mission on Oilseeds is to accelerate self-reliance in edible oils in the context of heavy reliance on imports of edible oil of the value of nearly